labour Force in Coal Subsidiaries

2454. SHRI P'ARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what was the strength of labour force of different coal-subsidiaries in the beginning of the year 1990-91;

(b) what is the number of workers who have since been retired during the last 3 years:

(c) whether it is a fact that large number of ghost workers had been identified and credit is being claimed by some officials of CIL; and

(d) whether it is not a fact that no such surplus workers are available anywhere, if not give the specific number of surplus workers on each subsidiary?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The strength of workforce of different subsidiaries of Coal India Limited at beginning of 1990-91 was as under:

Eastern Coalfields Limited	..	175375
Bharat Coking Coal Limited	..	163228
Central Coalfields Limited	..	97543
Western Coalfields Limited	..	80929
South Eastern Coalfields Limited	..	109950
Northern Coalfields Limited	..	12919
North Eastern Coalfields	..	5230
Central Mines Planning & Design Institute Limited	..	3020
Dankuni Coal Complex	..	590
Coal India Limited (HQ)	..	1131
Total :		649915

(b)

1990-91	1991-92	1992-93
7438	4998	5644

(c) No, Sir.

(d) Surplus workers have been identified as part of manpower budgeting in 3 subsidiaries of Coal India Limited as under:

Eastern Coalfields Limited	..	5.488
Bharat Coking Coal Limited	..	2,194
Central Coalfields Limited	..	3,166

निजी कोयला कम्पनियों द्वारा रेल वैगनों का निर्माण

2455 **श्री सोम पाल :**
श्री शारदा महन्ती :
श्री आनन्द प्रकाश गौतम:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कम्पनियों और कोयला व्यापारियों को खानों से कोयला उठाने के लिए रेल वैगनों का निर्माण करने तथा उन रेल वैगनों से कोयले की ढुलाई करने की अनुमति देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) रेलवे मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, रेलवे ने सितम्बर, 1992 में "ओन मोर वैगन" नामक एक योजना शुरू की है । यह योजना थोक उपभोक्ताओं से, जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसमें कोयला क्षेत्र भी शामिल है, से वैगनों का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए निवेश आमंत्रित करती है । यह योजना पक्षकारों को अपना रोलिंग स्टाक अनुमोदन प्राप्त वैगन निर्माताओं से या तो सीधे वैगन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वे भारतीय रेलवे से निर्धारित प्रभारों की अदायगी करके प्राप्त करने की अनुमति देती है । मालिकाना हक के लिए प्रस्तावित वैगन सामान्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले वैगन तथा विशेष श्रेणी वैगन हैं ।

जहां तक (एक्स-एन वैगनों) के कोयले का परिवहन किए जाने का संबंध है रेलवे मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे मालिकाना हक प्राप्त किए जाने के लिए, निजी पक्षकारों के लिए और थोक उपभोक्ताओं, जैसे तापीय विद्युत गृह और अन्य बड़े उपभोक्ता, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंध हैं, के लिए उपलब्ध हैं । किन्तु, इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोयला उपभोक्ताओं से निश्चित तौर पर कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Tie-up with Multinationals for Coal Supply to Power Projects

2456. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no private sector entrepreneur or multinational has approached the public sector coal mining industry for a tie-up to supply coal for its power projects;

(b) what are the reasons for our coal mining